No. **GAD-C(PA)-D (6)-2/2024**
Government of Himachal Pradesh
General Administration Department
(Parliamentary Affairs Department)

From

Chief Minister,
Himachal Pradesh, Shimla-2.

To

The Secretary,
Himachal Pradesh, Vidhan Sabha,
Shimla-171004.

Dated: Shimla-171002 the 2nd Sept 2024.

Subject:- **Introduction of "The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2024" (Bill No. 24 of 2024).**

Sir,

I have the honour to give the notice of my intention to introduce "The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2024" (Bill No. 24 of 2024) in the current session of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

I am, therefore, to request you to obtain the permission from Hon'ble Speaker to include the aforesaid Bill in the list of Business for introduction, consideration and passing the same in the current session. Three authenticated copies of the aforesaid Bill are enclosed herewith for appropriate action.

Yours faithfully,

(Sukhvinder Singh Sukhu)
Chief Minister, H.P.

2024 का विधेयक संख्यांक 24

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों के क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 6–ख का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 24

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2024 है। संक्षिप्त नाम।

2. मूल अधिनियम की धारा 6–ख की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :– धारा 6–ख का संशोधन।

"(2अ) इस धारा में अर्न्तविष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन पेंशन का हकदार नहीं होगा, यदि उसे संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन किसी भी समय अयोग्य घोषित किया गया है:

परंतु यदि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है, तो उसके द्वारा पहले से ली गई पेंशन की रकम ऐसी रीति में वसूल की जाएगी, जैसी विहित की जाए।"।

अधिप्रमाणित

मुख्य मन्त्री
हिमाचल प्रदेश

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 विधान सभा के सदस्यों के भत्ते और पेंशन प्रदान करने के दृष्टिगत अधिनियमित किया गया था। वर्तमानतः भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन विधायी सदस्यों के दलबदल को हतोत्साहित करने के लिए अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। इसलिए, सांविधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए; राज्य के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए; और इस सांविधानिक पाप (सिन) के निवारण के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

अधिप्रमाणित

मुख्य मन्त्री
हिमाचल प्रदेश

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
तारीख :....., 2024.

वित्तीय ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री ।

अधिप्रमाणित
मुख्य मन्त्री
हिमाचल प्रदेश

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख :....., 2024.

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) के उपबन्धों के उद्धरण।

धाराः

6–ख. पेन्शन.–(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने––

(क) विधान सभा के सदस्य, या

(ख) क्षेत्रीय परिषद् सदस्य, या

(ग) भागतः विधान सभा के सदस्य और भागतः क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य, या

(घ) (1) पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के तत्कालीन राज्य की विधान सभा; या

(2) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा, या

(3) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान परिषद, या

(4) भागतः एक और भागतः दूसरी के सदस्य जिन्हें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए पूर्ण क्षेत्र या उसके भाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया है,

(ङ) भागतः विधान सभा के सदस्य और भागतः, यथास्थिति, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य क्षेत्र के तत्कालीन राज्य या तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में पांच वर्ष तक किसी अवधि के लिए सेवा की है, प्रतिमास छतीस हजार रुपये पेन्शन संदत्त की जाएगी :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने प्रथम अवधि से अधिक अवधि के लिए उपयुक्त रूप से सेवा की है, वहां उसे प्रथम अवधि से अधिक अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एक हजार रुपए प्रतिमास

की अतिरिक्त पेन्शन संदत्त की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए वर्ष के किसी भाग को एक वर्ष के रूप में संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन संदेय अतिरिक्त पेन्शन के अवधारण करने के लिए अवधि की संगणना करते समय, हिमवाधित क्षेत्र (असमरूप क्षेत्र) में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की दशा में, जहां निर्वाचन आम चुनाव के लिए नियत दिन के पश्चात्वर्ती किसी भी दिन करवाए जाते हैं या करवाए जा सकेंगे, उस तारीख, जिसको आम चुनाव में विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और वह तारीख जिसको, हिमवाधित (असमरूप क्षेत्र) से निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, की मध्यवर्ती अवधि की भी गणना की जाएगी ।

स्पष्टीकरण.–पद "हिमवाधित क्षेत्र (असमरूप क्षेत्र)" से किन्नौर और लाहौल एवं स्पिती जिले तथा चम्बा जिला में तहसील पांगी और भरमौर अभिप्रेत है ।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन का हकदार कोई व्यक्ति–

(i) राष्ट्रपति या उप–राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाता है; या

(ii) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (1966 का 19) की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य बन जाता है; या

(iii) वेतन पर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम में या स्थानीय प्राधिकरण में नियोजित या राज्य सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकरण से अन्यथा कोई पारिश्रमिक पाने का हकदार हो जाता है; तो ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए जिसके वह ऐसा पद धारण किए रहता है या ऐसा सदस्य बना रहता है, या ऐसे नियोजित है या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहता है, उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति ऐसे पद धारण करने या ऐसा सदस्य रहने या ऐसे नियोजित रहने के लिए संदेय वेतन या जहां ऐसे व्यक्ति को संदेय खण्ड (iii) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक किसी भी दशा में उप–धारा (1) के अधीन उस संदेय पेन्शन से कम है, वह ऐसा व्यक्ति उस उप–धारा के अधीन पेन्शन के रूप में केवल अतिशेष को प्राप्त करने का हकदार होगा ;

(3) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने का हकदार कोई व्यक्ति अन्य पेन्शन पाने का भी हकदार है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अन्य पेन्शन के साथ–साथ उप–धारा (1) के अधीन, पेन्शन प्राप्त करने के हकदार होगा ।

(4) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणना करने में उस अवधि की भी गणना की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने मन्त्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 3) में यथा परिभाषित मंत्री के रूप में या विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संघ राज्य क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा की है।

(5) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन या पेन्शन लेने के हकदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो :–

(i) उसकी पत्नी/पति अपने जीवन काल में या पुनर्विवाह पर्यन्त; या

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति नहीं है तो व्यस्कता की आयु अभिप्राप्त करने पर्यन्त उसकी सन्तान और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह पर्यन्त, ऐसे व्यक्ति को यथा अनुज्ञेय पेन्शन के 50 प्रतिशत की दर पर पेन्शन लेने के हकदार होंगे।

परन्तु जहां इस उप–धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन लेने के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पेन्शन को समान अंश में लेने के हकदार होंगे ।

(5–अ) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (1–अ) के अधीन पेन्शन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु फरवरी, 1989 के सातवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पेन्शन नहीं ले सका वहां उसकी पत्नी, पति, अवयस्क संतान या अविवाहित पुत्रियों उप–धारा (5) के अधीन पेंशन लेने का हकदार होंगे, मानों कि ऐसा व्यक्ति फरवरी 1989 के सातवें दिन को जीवित था ।

(6) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु दिसम्बर, 1976 के इक्तीसवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पेन्शन नहीं ले सका, तो–

(i) उसके जीवन काल में या उसके पुनः विवाह करने पर्यन्त उसका पति/पत्नी, या

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति का पति/पत्नी नहीं है तो उसकी अवयस्क सन्तान व्यस्कता की आयु प्राप्त करने पर्यन्त और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह करने पर्यन्त,

उस राशि के बराबर पेन्शन जो ऐसे व्यक्ति ने पेन्शन के रूप में प्राप्त की होती, यदि वह दिसम्बर, 1976 के इक्तीसवें दिन को जीवित होता या तीन सौ पचहत्तर रुपए की राशि प्रति मास, इन दोनों में से जो अधिक हो, लेने का हकदार होगा/होगी:

परन्तु इस उप–धारा के अधीन तीन सौ पचहत्तर रुपए की उच्चतर सीमा जनवरी, 1986 के चौबीसवें दिन से मार्च, 1988 के इक्तीसवें दिन तक की कालावधि की पेन्शन के लिए लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां इस उप–धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उस पेन्शन को बराबर हिस्सों में लेंगे ।

(7) प्रत्येक व्यक्ति को जो इस धारा के अधीन पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन लेता है या पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन लेने का हकदार है, अनुज्ञेय पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन के अतिरक्त, उसी दर से पेन्शन पर मंहगाई राहत संदत्त की जाएगी जो राज्य सरकार के अन्य पेन्शन भोगियों को अनुज्ञेय है ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 24 OF 2024

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 6-B.

Bill No. 24 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2024

(As Introduced In The Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follow:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 2024. Short title.

2. In section 6-B of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:— Amendment of section 6-B.

"(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, a person shall not be entitled for pension under the Act, if he has been disqualified at any time under the Tenth Schedule of the Constitution:

Provided that if a person is disentitled for pension under this sub-section, the amount of pension already drawn by him shall be recovered in the manner as may be prescribed.".

Authenticated

Chief Minister
Himachal Pradesh

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 was enacted with a view to provide for allowances and pension to the Members of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh. Presently, there is no provision in the Act to discourage the defection of the legislative members under the Tenth Schedule of the Constitution of India. Thus, to achieve this Constitutional objective; to protect the mandate given by the people of the State, to preserve the democratic values; and to have deterrence towards this Constitutional sin, it has been necessitated to carry out amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Authenticated

Chief Minister
Himachal Pradesh

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:

THE....., 2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

Authenticated

Chief Minister
Himachal Pradesh

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:

THE....., 2024.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971 (ACT NO. 8 OF 1971) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Section:

6-B Pension.—(1) There shall be paid a pension of Rs. 36,000 per mensem to every person who has served for any period up to five years as,—

(a) a member of Assembly; or

(b) a member of the Territorial Council; or

(c) partly as a member of the Assembly and partly as member of the Territorial Council; or

(d) a member of-

(i) the Legislative Assembly of the erstwhile State of Patiala and east Punjab States Union; or

(ii) the Legislative Assembly of the erstwhile Punjab State; or

(iii) the Legislative Council of the erstwhile Punjab State; or

(iv) partly as a member of the one and partly as a member of the other;

who has been elected or nominated to represent the whole or the part of the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab re-organization Act, 1966.

(e) partly as a member of the Assembly and partly as a member of the Legislative Assembly of erstwhile State of Patiala and East Punjab State Union or the Legislative Assembly/ Council of the erstwhile State of Punjab, as the case may be:

Provided that where any person has served as aforesaid for a period exceeding first term, there shall be paid to him an additional pension of Rs. 1000/- per mensem for every year in excess of the period of first term; provided that for this purpose, the fraction of a year shall be counted as one year:

Provided further that while reckoning the period for the determination of the additional pension payable under the preceding *proviso* in the case of members elected from the constituencies comprised of snow-bound area (non-synchronous area) where the elections are or maybe conducted on any day subsequent to the day fixed for the general elections, the period intervening the date on which the oath is administered to the members elected to the Assembly in the general elections and the date on which the oath is administered to the members elected from the Snow-bound area (non-synchronous area) shall also be counted.

Explanation.—The expression "snow bound area (non-synchronous area)" means the area comprising Kinnaur, Lahaul and Spiti district and Pangi and Bharmaur tehsils in Chamba district.

(2) Where any person entitled to pension under sub-section (1),-

(i) is elected to the office of the President or Vice-President or is appointed to the Office of the Governor of any State or Administrator of any Union Territory; or

(ii) becomes a Member of any Legislative Assembly of a State or a Union Territory or Legislative Council of State or the Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of the Delhi Administration Act, 1966 (19 of 1996); or

(iii) is employed on a salary under the Central Government or any State Government or in a Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or local authority or becomes otherwise entitled to any remuneration from State Government, Corporations or local authority;

such person shall not be entitled to any pension under sub-section (1) for the period during which he continues to hold such office or as such member or is so employed or continues to be entitled to such remuneration:

Provided that where the salary payable to such person for holding such office or being such member or so employed or where the remuneration referred to in clause (iii) payable to such person is in either case less than the pension payable to him under sub-section (1) such person shall be entitled only to receive the balance as pension under that sub-section.

(3) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any pension, such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such other pension.

(4) In computing the number of years for the purposes of sub-section (1), the period during which a person has served as a minister, as defined in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 or the Speaker or the Deputy Speaker of the Assembly or the Chairman of the Territorial Council shall also be taken into account.

(5) Where any person who draws pension or is entitled to draw pension, under sub-section (1) and (1-A), dies,-

(i) his/her spouse during his/ her life time or till he/she remarries; or

(ii) if such person leaves no spouse his minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension at the rate of 50% of pension as admissible to such person:

Provided that where more than one person becomes entitled for pension under this sub-section all such persons shall draw the said pension in equal shares.

(5-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section where a person would have been entitled to draw pension under sub-section (1) or sub-section (1-A) of this section but for his death before the 7th day of February, 1989 he could not draw such pension, his spouse, minor children or un-married daughters shall be entitled to draw pension under sub-section (5), as if such person was alive on the 7th day of February, 1989.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where a person would have been entitled to draw pension, under sub-section (1) but for his death before the 31" day of December, 1976 he could not draw such pension,-

(i) his/her spouse during his/her life time or till he/she remarries; or

(ii) if such a person leaves no spouse, his/her minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension equal to a sum which would have been drawn by such a person as pension under this section as if such person was alive on the 31st day of December, 1976 or the sum of rupees three hundred and seventy five per mensem, whichever is higher:

Provided that the upper limit of rupees three hundred and seventy five shall not apply for the pension under this sub-section for the period from the 24th day of January, 1986 to the 31st day of March, 1988:

Provided further that where more than one person becomes entitled to pension under this sub-section, all such persons shall draw the said pension in equal shares.

(7) Every person who draws pension/family pension or is entitled to draw pension/ family pension, shall, in addition to the pension/family pension admissible under this section, be paid dearness relief in pension at the same rates as is admissible to other pensioners of the State Government.

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला—1018 जुड/2024—29—8—2024—175.